विदेश नीति पर लोक सभा में हुई बहस (नियम 193) पर प्रधानमंत्री का जवाब

दिनांक 12 मई, 2005
नई दिल्ली

12 मई, 2005 को विदेश नीति पर लोकसभा में हुई बहस पर प्रधानमंत्री के जवाब का प्रारंभिक संसद प्रतिलेखन।

प्रधानमंत्री (डॉ0 मनमोहन सिंह): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों पर 20 अप्रैल, 2005 को मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य पर टिप्पणी की है। उसके बाद से विदेशों से हमारे संबंधों में नई प्रगति हुई है जिससे मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

आरंभ में, मैं निरंतर और दृढ़ आत्म-सहमति, जो हमारी विदेश नीति के संचालन को दर्शाती है, पर गहरा संतोष व्यक्त करता हूं। ऐसा विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों द्वारा की गई अनेक टिप्पणियों में भी प्रदर्शित हुआ है।

महोदय, चीन के साथ हमारे संबंधों के महत्व के बारे में इस सदन में आम सहमति है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, हमारी सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर अत्यधिक महत्व देती है। हमारे इस बड़े पड़ौसी देश के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार करने की काफी संभावनाएं हैं। जहां तक सीमा प्रश्न के समाधान का संबंध है, मैं इस मुद्दे की जटिलता को मानता हूं। लेकिन इस संदर्भ में सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मापदण्ड और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करते हुए हमने चीन के साथ जो समझौता किया है, वह अत्यधिक महत्व रखता है।

महोदय, कुल मिलाकर अभी हाल ही में बढ़ते हुए हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नियमित प्रगति होती रही है जो अब सहयोग के बढ़ते क्षेत्रों और बढ़ती हुई आपसी समझ से परिलक्षित हो रही है। मैं चीन के साथ अपने संबंधों को प्रतिद्वंद्वियों के बीच के संबंधों जैसा नहीं मानता हूं बल्कि एशिया में और सम्पूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा तथा विकास को बढ़ावा देने में लगे सहयोगियों के बीच जैसे संबंधों की तरह समझता हूं।

महोदय, प्रो0 रामगोपाल यादव यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए थे। मैं भी समझता हूं कि हम ऐसे मुद्दों से निपटने जा रहे हैं जिनका काफी समकालिक महत्व है। कुछ खतरे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ये खतरे हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे, हालांकि हम इस जटिल स्थिति जिससे हमें निपटना है, को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों पर समझदारी से ध्यान देंगे।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने के महत्व पर जोर दिया है। हम सभी बकाया मुद्दों के संबंध में परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढ़ने की ईमानदारी से इच्छा रखते हैं।

माननीय सदस्यों ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को पूरी तरह बंद करने और नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू करने सहित सीमापार से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता पर ठीक ही जोर दिया है।

मैंने स्वयं राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ को बताया कि यदि निर्दोष पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध लगातार हो रही आतंकवादी कार्रवाई जारी रही तो मैं मौजूदा ठोस बातचीत की प्रक्रिया को आगे जारी रखने और शांति के मार्ग पर चलने की हमारी इच्छा को पूरा करने में भारतीय जनता की राय को अपने साथ नहीं ले पाऊंगा।

हमारी द्विपक्षीय शांति प्रक्रिया को आतंकवाद द्वारा बाधित न करने देने के राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा किए गए वायदे का हम स्वागत करते हैं। महोदय, हमारे दोनों देशों के बीच सभी बकाया मुद्दों का समाधान ढूंढ़ने के लिए हम दोनों शांति प्रक्रिया को वास्तव में न टूटने देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बेशक, सीमापार से घुसपैठ का मामला, विशेषकर जब कश्मीर में बर्फ पिघलने से ढके रास्ते गर्मी के मौसम में खुल जाते हैं, बहुत कुछ वास्तविक जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगा। हमें सावधान रहना है क्योंकि आतंकवादी तथा उग्रवादी अभी भी सक्रिय हैं। इस मामले में सतर्कता में कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

महोदय, शुक्र है कि किए गए व्यापक सुरक्षा उपायों के कारण श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा के संबंध में कोई और घटना नहीं घटी है और नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के लोगों पर इस सेवा का सकारात्मक प्रभाव कोई भी देख सकता है। हम अमृतसर और ननकाना साहब के बीच एक नई बस सेवा शुरू करने के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ पहले से ही तकनीकी बातचीत कर रहे हैं। हमें आशा है कि ये सेवाएं निकट भविष्य में शुरू हो जाएंगी। मैंने गुजरात को सिंध से जोड़ने वाले नये मार्गों को खोलने के संबंध में माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री की इच्छा पर ध्यान दिया है। हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे।

बगलिहार मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों की जांच करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के संबंध में विश्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। इस परियोजना पर काम बंद करने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता। माननीय सदस्यों को इस बात को समझना चाहिए कि यदि कोई भी एक पक्ष अभ्यावेदन देता है तो 1960 के सिंधु जल समझौते की शर्तों के तहत विश्व बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। हमने महसूस किया था कि विश्व बैंक का उल्लेख करना एक जल्दबाजी थी क्योंकि हमारे विशेषज्ञों के बीच आगे और तकनीकी चर्चाओं ने मतभेदों को कम किया है। मैंने स्वयं राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ से कहा था कि यदि पाकिस्तान इस परियोजना के किसी भी पहलू पर विश्वासोत्पादक और तकनीकी रूप से सत्यापित विरोध दर्ज करता है तो हम रूपरेखा में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब हम सभी सूचना तथा तकनीकी ब्यौरे उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं जिनकी जरूरत एक व्यापक मूल्यांकन करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ को हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत ने पिछले 45 वर्षों के दौरान

कभी भी सिंधू जल समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। हम इस समझौते का पूरी तरह से पालन करने का इरादा रखते हैं।

अनेक सदस्यों ने पाकिस्तान में भारतीय मछुआरों और अन्य भारतीय नागरिकों को बंदी बनाकर रखे जाने पर अपनी वेदना प्रकट की है। यह हमारी सरकार तथा हमारे विदेश मंत्री के प्रयासों का ही परिणाम है कि काफी बड़ी संख्या में इस बंधकों को मुक्त कर दिया गया है और जो पाकिस्तान में जेलों में अभी रह गए हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कब्जे में की गई मछली मारने की नौकाओं को छुड़ाने के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ संपर्क में हैं ताकि हमारे मछुआरे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।

हमने बंगलादेश के साथ अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सम्पर्कों को सुदृढ़ करके दोस्ती के अपने पारंपरिक सम्बंधों को जारी रखा है। यह हमारी हार्दिक इच्छा रहती है कि हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारी की आम सामूहिक चुनौती का सामना करने के लिए बंगलादेश की सरकार तथा वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करें। मैं श्री हन्नान मुल्ला द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रति बहुत गंभीर हूं। हम इस संबंध में गंभीर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम भारत के बागी समूहों द्वारा बंगलादेश के क्षेत्र का उपयोग किए जाने के संबंध में भी चिन्तित हैं। तथापि, मुझे पूरी आशा है कि हमारे दोनों देश इन मुद्दों को सुलझाने में मिलकर काम कर सकते हैं और मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे दोनों देशों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विकास की है और इस चुनौती से निपटने में हमें मिलकर काम करना पड़ेगा।

महोदय, भूटान के राजा और वहां की जनता के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंधों पर गर्व करने के सभी कारण हमारे पास मौजूद हैं। भूटान के राजा एक समझदार राजा हैं और उनके मार्गदर्शन में भूटान ने तीव्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भूटान के त्वरित विकास पर हमें गर्व है और हम उनकी प्रगति में सहयोगी बनकर अत्यन्त प्रसन्न हैं।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने नेपाल की स्थिति का उल्लेख किया है। नेपाल, जिसके साथ हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यताई संबंध रहे हैं, की सुरक्षा और विकास में हम बड़े साझीदार हैं। हमारी एकमात्र चिंता यह है कि नेपाल को आधुनिकीकरण के इस नए युग में, नेपाल की राष्ट्रीयता के दोनों स्तंभों नामतः संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ प्रवेश करना चाहिए। नेपाल का पड़ोसी होने के नाते और नेपाल के साथ हमारे विशेष संबंधों को देखते हुए हम उस देश की स्थिति के संबंध में काफी चिंतित हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम नेपाल में शांति, लोगों की सुरक्षा तथा नेपाल की जनता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में एक सहयोगात्मक बातचीत का रास्ता निकालें।

श्रीलंका की एकता और अखण्डता के प्रति अपनी परंपरागत दृढ़ प्रतिबद्धता पर हम कायम रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सारगर्भित बातचीत के जरिए तमिल अल्पसंख्यकों

सहित श्रीलंकाई समाज के सभी वर्ग टिकाऊ एवं सहयोगात्मक ढांचा तैयार करने में समर्थ होंगे जो उन्हें प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान की जिन्दगी जीने में समर्थ बनाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण एशिया को आर्थिक रचनात्मकता और उद्यम की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस बारे में सभी देशों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। इसी परिप्रेक्ष्य में, हमने अपने पड़ोसियों की ओर दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

अप्रैल का महीना हमारे विदेशी संबंधों के लिए अत्यधिक व्यस्त समय रहा है। अपने पिछले वक्तव्य के बाद हमने जापान के प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान का अपने यहां आतिथ्य-सत्कार किया। दिनांक 22 से 24 अप्रैल, 2005 को इंडोनेशिया के जकार्ता और बैंडांग में एफ्रो-एशियाई सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ का समारोह एक और महत्वपूर्ण घटना थी। मैं हाल ही में मास्को से लौटा हूं जहां मैंने फासीवाद और नाजीवाद के ऊपर विजय की 60वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह में भाग लिया। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने बहुमुखी द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। हम दोनों अपनी सामरिक भागीदारी को बनाए रखने के लिए सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं। दोनों देश आने वाले दिनों में इन संबंधों को व्यापक तौर पर तथा महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के लिए संयम से काम ले रहे हैं। मुझे राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का दो बार अवसर प्राप्त हुआ— जब हम पिछले सितम्बर में न्यूयार्क में मिले थे और जब हम पिछले सप्ताह के प्रारंभ में मास्को में एक-दूसरे से मिले थे। विदेश मंत्री के वाशिंगटन दौरे के दौरान एक इंडिया-यूएस एनर्जी पैनल की घोषणा की गई इससे दोनों देशों के नागर आणविक शक्ति सहयोग की सम्भाव्यता सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर कार्य आरंभ करने में मदद मिलेगी।

अमेरिका के साथ-साथ अन्य देशों में भी इस तथ्य को स्वीकार किया जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा स्रोत पर लागातार दबाव बढ़ रहा है और तेल की बढ़ती कीमतें शायद यहीं पर स्थिर हैं। भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक वृद्धि की बढ़ती हुई दर जिसकी गरीबी को दूर करने के लिए जरूरत है, को बनाए रखने के लिए ऊर्जा को एक दबाव बनने नहीं दिया जा सकता। हमारे लिए इस चुनौती से निपटने में आणविक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए, हम अपने देशी आणविक शक्ति कार्यक्रम को बनाए रखने और इसका विस्तार करने का इरादा रखते हैं। इससे विश्व भर में पारंपरिक ऊर्जा की आपूर्ति पर से भी दबाव कम होगा। चूंकि अप्रसार के क्षेत्र में भारत का रिकार्ड स्वीकार करने योग्य है और इसे विश्व भर में इसी रूप में जाना गया है इसलिए भारत के साथ आणविक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान प्रतिबंध पुराने और प्रति-उत्पादक हो गए हैं। मास्को में राष्ट्रपति श्री पुतिन के साथ मेरी मुलाकात के दौरान इस क्षेत्र के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों में भी भारत-रूस सहयोग पर मैंने संतोष जाहिर

किया और आशा व्यक्त की कि भारत और रूस के बीच सहयोग के क्षेत्र आने वाले वर्षों में बढ़ेंगे। इस वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति श्री बुश के आमंत्रण पर जब मैं वाशिंगटन जाऊंगा तो मैं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर अपनी उस बातचीत को जारी रखने का इरादा रखता हूँ जिस पर हमने मास्को में अपनी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान भी चर्चा की थी।

प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी के 28 तथा 29 अप्रैल को भारत दौरे ने हमारे दोनों देशों के बीच सतत तथा फलदायक बातचीत की शुरूआत की है। घनिष्ट राजनैतिक संबंधों और लोकतंत्र तथा संस्कृति के साझे मूल्यों के बावजूद भारत-जापान के आर्थिक संबंध अपनी क्षमता से काफी नीचे रहे हैं। हमारे संबंधों के इसी पहलू पर इस दौरे के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने संबंधों को और बढ़ाने के अनेक निर्णय लिए। जापान, मुंबई तथा दिल्ली और दिल्ली तथा कोलकाता के बीच तीव्र गति वाले रेल माल कॉरिडोर स्थापित करने में हमें सहयोग देने हेतु विचार करने पर सहमत हो गया है। जापान भारतीय शिक्षण संस्थाओं में जापनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराएगा ताकि हमारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जापान के विशाल और बढ़ते हुए सॉफ्टवेयर बाजार का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

माननीय सदस्यगण उपनिवेशवाद का अंत करने, एशिया और अफ्रीका के नवगठित राष्ट्रों के बीच एकता का भाव भरने और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करने में 1955 के एफ्रो-एशियन सम्मेलन द्वारा दिए गए ऐतिहासिक सहयोग को याद करें। 50 वर्ष पहले उस बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा इस सम्मेलन के दौरान अनेक नेताओं से हुई मुलाकात में मैंने की। भारत को एशियाई देशों की ओर से बोलने का विशिष्ट आदर दिया गया था और हमारी आवाज को सम्पूर्ण विश्व के नेताओं के काफी बड़े समूह द्वारा सम्मान के साथ सुना गया। महोदय, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस सम्मेलन ने विकासशील देशों के बीच एकता और गहरी दोस्ती की भावना को पुनः जागृत किया है। इस सम्मेलन में इन भावनाओं को सहयोग के व्यावहारिक कार्यक्रमों में परिवर्तित करने, एक दूसरे की अच्छी बातों का लाभ उठाने और एक अधिक समान अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में अत्यधिक सामूहिक क्रय-शक्ति का उपयोग करने का संकल्प जताया गया।

महोदय, मैंने उपस्थित नेताओं से आग्रह किया कि वे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करने वाले क्षेत्र का विस्तार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में आए असंतुलनों को दूर करने के उपाय सुझायें। मैंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो कि एक बड़ी वैश्विक समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है, का सामना करने के उपायों पर हमारा अपना अलग दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण "सभ्यताओं के बीच एक अर्थपूर्ण बातचीत" प्रारंभ करने तथा उसे बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित है न कि तथाकथित *"सभ्यताओं के बीच टकराव"* के सिद्धांत का इस्तेमाल करने पर।

बैडांग में एशियाई नेताओं के साथ मेरी बैठकों ने मुझे **"पूर्वोन्मुख नीति"** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराने और दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ घनिष्ट संबंध बढ़ाने का एक और अवसर भी प्रदान किया है। हम 21वीं शताब्दी को वास्तव में एशियाई शताब्दी बनाने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महोदय, मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के देशों ने ऐसी ही संभावनाएं व्यक्त की हैं जब उन्होंने इस वर्ष आगे चलकर होने वाले पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। हम पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास भी कर रहे हैं।

हमने अपने नए *"स्ट्रैटेजिक सहयोग"* के जरिए यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को नया रूप देने की ओर भी कदम बढ़ाया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर की सितम्बर में आगामी भारत यात्रा से हमें यूरोपीय संघ और इंग्लैण्ड, दोनों के साथ अपने स्ट्रैटेजिक संबंधों को ठोस स्वरूप प्रदान करने का एक और अवसर मिलेगा।

मैं इस जुलाई में स्काटलैंड के ग्लेनेजल्स में जी-8 समूह के देशों की बैठक में भाग लेने के अवसर की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इससे हमें अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में भारत का भाग लेना वैश्विक समुदाय में और सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी स्थिति की एक महत्वपूर्ण पहचान है।

मैंने अन्य मित्र देशों के घनिष्ट सहयोग से संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार लाने हेतु भारत के प्रयासों को भी दर्शाया है। 25 और 26 अप्रैल, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान की भारत यात्रा ने हमें संयुक्त राष्ट्र में हुए वर्तमान घटनाक्रमों की समीक्षा करने और हमारी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान से मिलकर बने ग्रुप-4 देश सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण पुनर्गठन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो तिहाई से अधिक बहुमत जुटाने के हमारे साझे उद्देश्य को प्राप्त करने में अत्यंत घनिष्टता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या, सक्रिय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करने के लम्बे इतिहास और अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने की पात्रता रखता है। हमारा यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने से इसे और अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बहुपक्षीय निर्णय लेने तथा कार्य करने में और अधिक सक्षम बनना चाहिए।

हम इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं कि स्थिति अत्यंत जटिल है और अनेक शक्तिशाली देश इस परिवर्तन के विरोध में हैं। तथापि, अनेक वर्षों में यह पहली बार हुआ

है कि संयुक्त राष्ट्र में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए एक विशेष संवेग का निर्माण हुआ है। यह एक सुनहरा अवसर है कि हमें विकासशील देशों के रूप में इसका लाभ उठाने के हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

माननीय सदस्यगण, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें काफी तेजी से बदलाव आ रहा है और जिसमें प्रतिदिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभरने से दुनिया के शेष देशों में हमारे संबंधों का दायरा बढ़ा है। हमारे लिए हमारी विदेश नीति की प्रमुख चुनौती एक क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण करने और उसे बनाए रखने में निहित है जो हमें आर्थिक वृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने, भारतीय उद्यमशीलता के लिए और अधिक अवसरों का सृजन करने और भारत को विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की इसकी विशाल छिपी हुई क्षमता को पहचानने में मदद देगी। इसके परिणामस्वरूप, गत वर्ष में हमारी सरकार ने अपने पड़ोसी देशों विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने ऊर्जा कुटनीति पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक कुटनीति पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया है। ऊर्जा संसाधनों के लिए हमारी खोज ने हमें सूडान जैसे देशों में बड़े निवेश करने और मध्य एशिया में संभावनाएं तलाशने की ओर अग्रसर किया है। राजनीति और अर्थव्यवस्थाएं अब एक राष्ट्र के रूप में भारत के सम्पूर्ण हितों को साधने में साथ-साथ चलनी चाहिए।

महोदय, मैं वायदा करता हूँ कि जहां एक ओर हम पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित विदेश नीति के सिद्धांतों का अनुसरण करने के प्रति निष्ठावान रहे हैं और पिछली आधी शताब्दी से भी अधिक अवधि के दौरान हमारे देश ने इसका लगातार पालन किया है वहीं दूसरी ओर, हम तेजी से बदलती विश्व-व्यवस्था द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई बाध्यताओं के प्रति भी सतर्क हैं। इसके अलावा, हम एक राष्ट्र के रूप में, अपने समक्ष नई उभरती हुई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता तथा योग्यता रखते हैं। इसका श्रेय आज विश्व में भारत के ऊंचे स्थान को जाता है कि हमारा देश विश्व भर के विश्वस्तरीय नेताओं के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में उभरकर सामने आया है। एक विश्वासी तथा एकजुट राष्ट्र के रूप में भारत की यह छवि उस सतत राजनीतिक आम-सहमति से उभरकर सामने आई है जो हमेशा से हमारी विदेश नीति का प्रतीक चिह्न रही है।

महोदय, मेरा मानना है कि राष्ट्रों के समूह में जिस बात का भारत प्रतिनिधित्व करता है, यह उसकी एक पहचान है। मौलिक मानवाधिकारों और कानून के सम्मान पर आधारित एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के निर्माण के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता ने हमें इस युग में एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि विश्व के सभी राष्ट्र एक दिन उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। ये सिद्धांत हमें राष्ट्रत्व की इन जड़ों को पोषित करने की प्रतिबद्धता की ओर संकेत करते हैं। मैं वायदा करता हूँ कि हमारी सरकार भारत के भाग्य का निर्माण करने के स्वप्न को पूरा करने हेतु कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हार्दिक सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए मैं इस सदन को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा।

धन्यवाद।